आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 01.02.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
- छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक में उत्तराखण्ड ने विकास से जुड़े 13 मुद्दे रखे, केंद्र सरकार ने सकारात्मक कार्यवाही का दिया आश्वासन।
- अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा अथरबनी गांव में फैमिली एडॉप्शन कार्यक्रम आयोजित, एमबीबीएस छात्रों को मिलेगा सामुदायिक स्वास्थ्य का व्यावहारिक अनुभव।
- उत्तराखण्ड बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च तक; 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल।

केंद्रीय बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। बजट तैयार करने से पहले, वित्त मंत्री ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें कीं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक बजट पूर्व परामर्श बैठकें कीं और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। एक रिपोर्ट–

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। उन्होंने 2019 में वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। अपने बजट भाषण में वह अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास के रूपरेखा के साथ–साथ सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगी। बजट तैयार करते समय केंद्र सरकार द्वारा युवाओं समेत आम नागरिकों से अलग–अलग माध्यमों के जरिए सुझाव मांगे गए थे जिसकी झलक केंद्रीय बजट 2026–27 में देखने को मिलेगी। बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट से जुड़े सभी दस्तावेज यूनियन बजट मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 30 कॉलेज छात्रों से भी संवाद करेंगी। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था जो 2 अप्रैल तक चलेगा।

मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक

छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक में उत्तराखण्ड ने विकास से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखा। बैठक में उत्तराखण्ड की ओर से कुल 13 विषय प्रस्तुत किए गए, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक रहे। राज्य द्वारा रखे गए विषयों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। एक रिपोर्ट–

इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सामाजिक–आर्थिक विकास, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, लंबित मामलों के समाधान और राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। उत्तराखण्ड की ओर से विकास, आधारभूत संरचना और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा वन एवं पर्यावरण, आरके सुधांशु ने बताया कि बैठक में उत्तराखण्ड के सभी विषय ठोस तर्कों और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ रखे गए। उन्होंने कहा कि पूर्व में वाराणसी में हुई परिषद की बैठक में उठाए गए 11 बिंदुओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिनमें खाद्य सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कुपोषण की रोकथाम, आपातकालीन सेवा 112, सहकारिता, आयुष्मान भारत योजना और गांवों के पास बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े विषय शामिल थे।

बैठक के दौरान राज्यों की ओर से अपनाई जा रही नवाचारपूर्ण पहलों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी चर्चा हुई। उत्तराखण्ड ने राज्य–से–निवेश आपूर्ति श्रृंखला योजना, डिजिटल शिक्षा प्रबंधन प्रणाली और जल संवर्द्धन से जुड़े कार्यों को अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे सराहा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बैठक में मिले सुझावों और सहमति के आधार पर राज्य में विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि इसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे।

लाइव प्रसारण

भारतीय जनता पार्टी आम बजट को आमजन तक व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए विशेष आयोजन कर रही है। इसके तहत प्रदेश पार्टी मुख्यालय से लेकर मंडल स्तर तक 78 स्थानों पर एलईडी के माध्यम से बजट अभिभाषण का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय, विधानसभा और मंडलों में बजट भाषण का सीधा प्रसारण होगा। इसके बाद पत्रकार वार्ता और गोष्ठियों के माध्यम से बजट पर चर्चा और जनसंवाद किया जाएगा।

समीक्षा

सचिव आवास विकास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की। हरिद्वार में हुई बैठक में उन्होंने आवासीय योजनाओं, राजस्व संग्रह और लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली तथा आवासीय आवेदनों से जुड़ी आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। साथ ही मास्टर प्लान के अनुसार कार्य, पार्किंग व सौंदर्यकरण के रखरखाव और थर्ड पार्टी ऑडिट के निर्देश दिए गए।

बैठक के बाद सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि परियोजना का लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। यूनिटी मॉल में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के तहत स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जा रही है। सचिव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी विकास योजनाओं को समयबद्ध और जनहित में लागू करना है।

बोर्ड परीक्षा

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च तक एकल पाली में आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और नकलविहीन संचालन को लेकर परिषद सभागार में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित की गई।

बैठक में दोनों मंडलों के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और संकलन केंद्रों के उप नियंत्रक शामिल हुए। इस दौरान परिषद सचिव ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षाएं पूरी सतर्कता, गोपनीयता और नकलविहीन माहौल में कराई जाएं।

गौरतलब है कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में कुल 2 लाख 16 हजार 109 परीक्षार्थी शामिल होंगे। राज्यभर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल एक हजार 261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं।

फैमिली एडॉप्शन कार्यक्रम

अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा हवालबाग विकासखंड के अथरबनी गांव में फैमिली एडॉप्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम एनएमसी मानकों के तहत एमबीबीएस छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य का व्यावहारिक अनुभव देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

इसके तहत एमबीबीएस प्रथम सेमेस्टर के छात्र अगले तीन वर्षों तक प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को गांव जाकर गोद लिए गए परिवारों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। विभाग के चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद इकबाल ने बताया कि एमबीबीएस पांचवें बैच के 100 छात्र–छात्राओं ने फैमिली एडॉप्शन की जिम्मेदारी ली है, जिससे हर परिवार से एक छात्र जोड़ा जाएगा।

ग्राम प्रधान विनोद जोशी ने इस पहल को ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया। ग्रामीणों ने भी कार्यक्रम की सराहना की।

फटकार/समीक्षा

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित जिलावार समीक्षा बैठक को लेकर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में जिलाधिकारी ने जिला योजना, राज्य सेक्टर और केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और कम खर्च करने वाले विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व और गृह विभाग के साथ–साथ विभिन्न विकासात्मक कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा भी की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंच सके।

गुरु रविदास जयंती

गुरु रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने छुआछूत, सामाजिक असमानता और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई और प्रेम, करुणा तथा सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे संत रविदास जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएँ और समाज की भलाई के लिए कार्य करें।